रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262070
CG-DL-E-28032025-262070

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1490] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947
No. 1490] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2025

का.आ.1508(अ).—केंद्रीय सरकार, समुद्री जल दस्युता रोधी अधिनियम, 2022 (2023 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 के अधीन प्रदत्त और इस संबंध में मक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के सेशन न्यायालयों को अभिहित न्यायालय के रूप में नाम्रिदिष्ट करती है, अर्थात्:-

क्रम संख्या	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का नाम		अभिहित सेशन न्यायालय
1.	गुजरात	-	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का न्यायालय ,पोरबंदर।
2.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	-	प्रधान जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, दीव और प्रधान जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, दमन।
3.	महाराष्ट्र	-	शहर सिविल और सेशन न्यायालय, मुंबई की मुख्य शाखा कोर्ट रूम नंबर 28।
4.	गोवा	-	जिला न्यायाधीश-2 और अपर सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, मडगांव , दक्षिण गोवा।

5.	कर्नाटक	-	विशेष न्यायालय के रूप में प्रधान जिला और सेशन न्यायालय दक्षिण कनाड़ा मंगलुरू कर्नाटक ।
6.	केरल और लक्षद्वीप	-	अपर विशेष सेशन न्यायालय - (विशेष पुलिस स्थापन या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों) III, एर्नाकुलम।
7.	तमिलनाडु और पुडुचेरी	-	प्रधान न्यायाधीश, सिटी सिविल न्यायालय, चेन्नई और प्रधान जिला न्यायालय, थूथुकुडी ।
8.	आंध्र प्रदेश	-	बारहवां अपर जिला और सेशन न्यायालय, विशाखापत्तनम ।
9.	ओडिशा	-	सेशन न्यायाधीश न्यायालय, जगतसिंहपुर ।
10.	पश्चिम बंगाल	-	अपर सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, हल्दिया, पूर्व मेदिनीपुर ।
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	दक्षिण अंडमान जिले में अपर जिला और सेशन न्यायधीश का न्यायालय न्यायाधीश, पोर्ट ब्लेयर और अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, मायाबंदर ।

[फा. सं. 1/3/2023- तटीय सुरक्षा]

पौसुमी बसु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2025

S.O. 1508(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Maritime Anti-Piracy Act, 2022 (3 of 2023), hereinafter referred to as said Act, and all other powers enabling in this behalf, the Central Government for the purposes of the said Act, hereby designates the Sessions Courts of the following State Governments and Union territory Administrations as mentioned against each as Designated Courts, namely: -

Serial number	Name of state or Union territory Administrations		Designated Sessions Court
1.	Gujarat	-	Court of Additional District Judge, Porbandar.
2.	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	-	The Court of Principal District and Sessions Judge, Diu and the Court of Principal District and Sessions Judge, Daman.
3.	Maharashtra	-	Court Room No.28 at Main Branch at City Civil and Sessions Court, Mumbai.
4.	Goa	-	Court of the District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Margao South, Goa.
5.	Karnataka	-	Principal District and Sessions Court, Dakshina Kannada Mangaluru as Special Court, Karnataka.
6.	Kerala and Lakshadweep	-	The Additional Special Sessions Court (Special Police Establishment or Central Bureau of Investigation)-III, Ernakulam.
7.	Tamil Nadu and Puducherry	-	Principal Judge, City Civil Court, Chennai and the Principal District Court, Thoothukudi.
8.	Andhra Pradesh	-	Court of XII Additional District and Sessions Court, Visakhapatnam.
9.	Odisha	-	Court of Sessions Judge, Jagatsinghpur.
10.	West Bengal	-	Court of Additional Sessions Judge, Haldia, Purba Medinipur.
11.	Andaman and Nicobar Islands	-	The court of Additional District and Sessions Judge, Port Blair, South Andaman District; and the Additional District and Sessions Judge, Mayabunder.

[F. No. 1/3/2023-Coastal Security]

PAUSUMI BASU, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA